सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

मोहन यादव की जातिवादी सोच से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल!

» Pg12

कानपुर, मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 272, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड सुगर भूमि घोटाले की गहरी जड़ों में भू-माफिया से ... » Pg02

यूपी में 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों की चांदी

मुख्यमंत्री योगी ने दिया दिवाली से पहले तोहफा!

बोनस देने का किया ऐलान, बोले सीएम- भुगतान समय से होना चाहिए, सरकार पर बढ़ेगा 1,022 करोड़ का भार

» बोले-विकास के लिए इन कर्मचारियों की भूमिका होती है अति महत्वपूर्ण।

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा सात हजार रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपये का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग 1,022 करोड़ रुपये आएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें। राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600 रुपये- 1,51,100 रुपये) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते 29 सितम्बर, 2025 द्वारा बोनस प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बोले सीएम-ग्राम पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं, विकास की आत्मा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बयान के मुताबिक, बैठक में प्रस्तुत किये गए विवरण के अनुसार पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

नया ट्विस्ट

सुसाइड नोट में डीजीपी को बताया ईमानदार अधिकारी

हरियाणा में अब एएसआई ने दी जान, पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप!

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

रोहतक। हरियाणा पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) ने सोमवार रात को रोहतक स्थित अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई है। मृतक एएसआई ने तीन पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा है, जिसमें उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरन कुमार पर ही भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, डीजीपी को उन्होंने ईमानदार बताया है।

मृतक एएसआई जो रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे, का शव उनके सरकारी क्वार्टर में फर्श पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में गोली का पता चला, जो आत्महत्या की ओर इशारा करता है। पुलिस ने मौके से सर्विस रिवॉल्वर, सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद किया है। नोट में एएसआई ने लिखा है कि उन्होंने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत दी है और अपने परिवार के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो मैसेज में भी आईपीएस पूरन कुमार पर दबाव बनाने और भ्रष्टाचार में फंसाने के आरोप दोहराए गए हैं।

वीडियो में संदीप कहते हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर बहुत ईमानदार आदमी हैं। ये आईएएस लॉबी ये चाहती है कि ये डीजीपी चले जाएं और हम मलाई खाएं। ये देश का नाश कर रहे हैं। यह घटना हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार के आरोपों को नई हवा दे रही है। हाल ही में एक अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाईएस पूरन ने भी चंडीगढ़ में आत्महत्या की थी, जिससे विभाग पहले ही सदमे में था। डीजीपी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, हम इस घटना की गहन जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने साइट का निरीक्षण किया है और नोट की हैंडराइटिंग की पुष्टि हो चुकी है।

बता दें कि वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले की जांच कर रहे एएसआई ने ही अब जान दे दी है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसलिए अब एएसआई द्वारा लगाए गए नए आरोपों से कुमार की मौत के मामले की चल रही जाँच और जटिल होने के आसार बढ़ गए हैं।

सुरार भूमि घोटाले की गहरी जड़ों में भू-माफिया से लेकर लेखपाल तक

स्वराज इंडिया ने सरकारी भूमि पर कब्जे का किया था बड़ा खुलासा

» एसडीएम के आदेश के बाद सख्ती, भूमाफियाओं पर जल्द गाज गिरने की उम्मीद

» सुरार में ऊसर भूमि पर अवैध प्लाटिंग का मामले की जांच से खुलेंगी कई परतें

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरार की ऊसर भूमि पर भू-माफिया वीर बहादुर यादव और महेंद्र यादव के कब्जे और अवैध प्लाटिंग का मामला अब प्रशासनिक जांच के घेरे में है। ग्राम प्रधान पंकज यादव ने एसडीएम सदर को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की आराजी संख्या 607, 608, 610 और 613 की भूमि पर कब्जा कर प्लाटिंग शुरू कर दी।

प्रधान के अनुसार, इस अवैध कार्य में मौजूदा लेखपाल अनिल कुमार की मिलीभगत रही, जिन्होंने कथित तौर पर मोटी रकम और महिला मित्र के नाम उपहार स्वरूप एक प्लॉट लेकर भूमाफियाओं के पक्ष में मिथ्या रिपोर्ट लगाई। स्वराज इंडिया द्वारा लगातार रिपोर्टिंग के बाद यह मामला

अवैध प्लाटिंग कर्ता वीर बहादुर यादव

जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ने जांच के आदेश दिए और जांच की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार सचेंडी रिचा सचान को सौंपी।

भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा

जांच अधिकारी रिचा सचान ने स्वराज इंडिया से कहा कि मौके पर जो अनैतिक पाया गया उसे भूमाफियाओं के द्वारा सुधारने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल भूमि खाली कराना पर्याप्त कार्रवाई मानी जाएगी? यदि सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग की गई, तो क्या भू-माफिया और भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या एक बार फिर सुधरने का आश्वासन ही सजा का विकल्प बन जाएगा? वहीं जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों और सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

आलोक दुबे प्रकरण से जुड़ा सुरार कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि सुरार ग्राम पंचायत वही क्षेत्र है जहां कभी तत्कालीन कानूनगो आलोक दुबे तैनात थे। वही आलोक दुबे जिन पर फर्जी रजिस्ट्री, करोड़ों की अवैध संपत्ति और दस्तावेजी हेराफेरी के आरोप सिद्ध हुए हैं।

पुलिस ने आलोक दुबे, लेखपाल अरुणा द्विवेदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।

राजस्व विभाग के इसी भ्रष्ट नेटवर्क के सहारे अब वीर बहादुर यादव और महेंद्र यादव जैसे भू-माफिया फल-फूल रहे हैं।

सवाल यह है कि क्या इस बार प्रशासन वास्तव में ईमानदारी से जांच करेगा या फिर

एक और आलोक दुबे के जैसी कहानी बनकर फाइलों में दफन हो जाएगी जो बाद में खुलेगी।

कफ सीरप और नींद की गोलियों के काले कारोबार पर फिर छापा

» अनवरगंज के सील मेडिकल स्टोर से मिलीं 2 हजार शीशियां कफ सीरप और 9 हजार नींद की गोलियां

» लुधियाना से आई नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई के बाद कानपुर में औषधि विभाग सतर्क, जांच जारी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में नकली और नशे में उपयोग होने वाली दवाओं के खिलाफ औषधि विभाग की कार्रवाई

लगातार तेज होती जा रही है। रविवार को बिरहाना रोड की नील वाली गली में मानक के विपरीत दवा निर्माण और पैकिंग का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अनवरगंज क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाएं बरामद की हैं।

औषधि निरीक्षक ओ.पी. सिंह, अजय कुमार संतोषी और परमेश द्विवेदी की टीम ने अनवरगंज स्थित 'बालाजी जी मेडिकल स्टोर' से करीब दो हजार कफ सीरप की शीशियां और नौ हजार नींद की गोलियां पकड़ीं। यह सारी दवाएं बिना बिल के पाई गईं, जिन्हें तुरंत सील कर दिया गया। तीन कफ सीरप और एक प्रकार की गोली के सैंपल जांच के लिए वाराणसी स्थित राजकीय औषधि प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने बताया कि स्टोर संचालक किसी भी दवा का बिल नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने बताया कि दवाएं लखनऊ से खरीदी गई थीं। जांच टीम को स्टोर के अंदर बड़ी मात्रा में अवैध भंडारण भी मिला। अधिकारियों ने कहा कि दस्तावेज न मिलने की स्थिति में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लुधियाना से आई नारकोटिक्स टास्क टीम ने कानपुर में छापा मारकर 28.85 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में नकली दवाएं व पैकिंग सामग्री जब्त की थी। उसके बाद से शहर में लगातार औषधि विभाग की टीमें छापेमारी अभियान चला रही हैं। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक नकली और नशे में प्रयोग होने वाली दवाओं का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।

पनकी नहर की बाउंड्री वॉल पर दिखा विशालकाय अजगर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र की पनकी नहर की बाउंड्री वॉल पर शनिवार रात विशालकाय अजगर दिखने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया है और वन विभाग से अजगर को पकड़ने की मांग की गई है।कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र की पनकी नहर के पास शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब नहर की बाउंड्री वॉल के ऊपर एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं, क्षेत्रीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र की पनकी नहर की बाउंड्री वॉल में अजगर रात के अंधेरे में कुंडली मारकर बैठा और रेंगता हुआ दिखाई दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में अजगर देखे जाने की खबरें आ रही थीं, लेकिन रात में उसे इतने करीब से देखने के बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया है।घटना के बाद कुछ क्षेत्रीय लोगों ने अजगर का वीडियो बना लिया, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की गुहार लगाई है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

हिस्ट्रीशीट की कॉपी न देने पर कानपुर पुलिस से हाईकोर्ट नाराज

» कोतवाली इंस्पेक्टर 15 अक्टूबर को कोर्ट में तलब

भाजपा नेता व हैट्रिक पार्षद अभिषेक गुप्ता की याचिका पर सुनवाई, न्यायालय ने कहा— हिस्ट्रीशीट खोलने की सूचना देना अनिवार्य

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बेलगाम पुलिसिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कानपुर के भाजपा नेता व हैट्रिक पार्षद अभिषेक गुप्ता उर्फ़ मोनू की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ़ कहा कि जब किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट खोली जाती है, तो उसकी प्रति संबंधित व्यक्ति को देना आवश्यक है।

अभिषेक गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उनके खिलाफ सात मामलों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोल दी, मगर उसकी प्रति उन्हें अब तक नहीं दी गई। साथ ही, पुलिस लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

पार्षद अभिषेक गुप्ता 'मोनू'

न्यायालय ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि कोतवाली थाने में एचएस संख्या 01-ए के रूप में हिस्ट्रीशीट खोली गई है और इसकी जानकारी प्रेस नोट के ज़रिए दी गई है, लेकिन उसकी आधिकारिक प्रति याची को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर न्यायमूर्ति जे.ज़े. मुनिर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के विरुद्ध है।अदालत ने आदेश दिया है कि थाना प्रभारी 15 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होकर हिस्ट्रीशीट की प्रति साथ लेकर आएं। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया कि इस आदेश की प्रति आज ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के माध्यम से थाना प्रभारी तक पहुंचाई जाए।

हाईकोर्ट का यह कदम एक बार फिर इस बहस को हवा दे रहा है कि क्या पुलिस हिस्ट्रीशीट खोलने के नाम पर अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल कर रही है। अदालत का यह सख्त रुख अब कानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा बीएनएसडी शिक्षा निकेतन कानपुर का नाम

छात्र अमित कुमार ने राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में हासिल किया तीसरा स्थान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर/लखनऊ।कानपुर के लिए गर्व का क्षण – युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue के अंतर्गत 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में देशभर से चयनित प्रतिभागियों के मध्य हुई राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में बी.एन.एस.डी. शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज, बेनाझाबर के कक्षा-12 के प्रतिभाशाली छात्र मै. अमित कुमार ने संपूर्ण देश में तृतीय स्थान प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर सोमवार को लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विद्यालय की प्रबंध समिति एवं बी.एन.एस.डी. शिक्षा निकेतन के प्रधानाचार्य बृजमोहन सिंह ने अमित कुमार की इस गौरवशाली सफलता पर अपार हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।विद्यालय प्रशासन ने कहा कि अमित की यह उपलब्धि न केवल विद्यालय के लिए बल्कि पूरे जनपद कानपुर के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेगी। अमित कुमार की यह उपलब्धि साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और लगन से नई ऊँचाइयों को छुआ जा सकता है।

नगर निगम कानपुर ने हटाए 800 अवैध होर्डिंग्स और बैनर

» अवैध विज्ञापनों और अतिमणक्रम पर चला नगर निगम का डंडा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।महापौर के निर्देशन और प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कानपुर नगर निगम द्वारा शहर को अवैध विज्ञापनों और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को व्यापक कार्रवाई की गई।नगर निगम की टीमों ने शहर के सभी जोनों में प्रभावी अभियान चलाते हुए अवैध व अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन पटों, बोर्डों और बैनरों को हटाया। निगम की कार्रवाई के दौरान कुल 800 अवैध विज्ञापन सामग्री को हटाया गया, जिसमें 650 कियोस्क, 65 बिलबोई और 85 रोड क्रॉस बैनर शामिल रहे।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जनमानस को स्वच्छ, सुन्दर और अव्यवस्थित विज्ञापनों से मुक्त शहर प्रदान करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि अवैध विज्ञापन पटों एवं यूनीपोल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, नगर निगम राजस्व वसूली लक्ष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करने वाले सभासदों के चेहरे खिले

नगर पालिका ईओ के खिलाफ कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज

मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सच सामने आया

शासन के एक पत्र से राजनैतिक सरगर्मी बढ़ी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर नगर पालिका में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप आखिर अब सच्चाई की कगार तक पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज दो अलग-अलग शिकायतों की जांच में जो सच सामने आया है, उसने नगर पालिका की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। शासन ने इस मामले को गंभीर मानते हुए ईओ अंजनी मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हाल ही में जारी पत्र (संख्या-2908-नौ-4-2025) में नगर निकाय निदेशालय को नियमानुसार कार्रवाई कर शासन को अवगत कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कई निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं पाई गई और अभिलेखों का रख-रखाव बेहद लापरवाही भरा पाया गया। जनरेटर की लॉगबुक से लेकर निर्माण सामग्रियों के पुनः उपयोग तक, हर जगह अनियमितता का जाल फैला मिला। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एसडीएम (न्यायिक) बिल्हौर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने 13 बिंदुओं पर गंभीर खामियां उजागर कीं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में ईंटों, लाइटों और अन्य सामग्रियों के पुनः उपयोग में नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना और भूख हड़ताल करने वाले भाजपा सभासद अतुल तिवारी का कहना है कि शासन ने आखिर हमारी आवाज़ सुनी। वर्षों के संघर्ष के बाद जांच रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर की है। अब बस कार्रवाई का इंतजार है। स्थानीय स्तर पर यह मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है। विरोधी खेमे में जहां खुशी की लहर है, वहीं नगर पालिका प्रशासन पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है। अब सभी की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या बिल्हौर की ईओ पर गिरेगी कार्रवाई की गाज या फाइलें फिर किसी अलमारी में कैद हो जाएंगी?

कई दिनों तक चला था धरना

भाजपा सभासद अतुल तिवारी ने पालिका के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दो और सभासदों ने भी उनके साथ आवाज़ बुलंद की। पालिका गेट के बाहर कई दिनों तक धरना चला। इसके बाद भाजपा नेता आदेश तिवारी के समर्थन के बाद दर्जनों लोग आंदोलन में शामिल हुए। कड़ाके की सर्दी में भी धरना जारी रहा। अंततः डीएम जीतेन्द्र प्रताप सिंह व विधायक राहुल बच्चा सोनकर के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ।

चेयरमैन ने आजमाए पैंतरे

सूत्रों के मुताबिक ईओ के इशारे पर चलने वाले चेयरमैन इकलाख ने धरना खत्म कराने के लिए कई राजनीतिक प्रयास कर कई पैंतरे आज़माए थे। सूत्र बताते हैं भाजपा नेताओं के घर तक हाजिरी दी, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में कुछ सभासदों को अपने पक्ष उतारने में सफल हुए। जिससे भ्रष्टाचार की आवाज एकतरफा नही हो पाई।

...तो फिर इतिहास रच जाएगा

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शासन द्वारा मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट से साफ है कि अब कार्रवाई लगभग तय है। अगर पालिका ईओ पर कानूनी शिकंजा कसता है, तो यह बिल्हौर पालिका इतिहास में पहली बड़ी कार्रवाई होगी। जिसकी लपटों से खुद चेयरमैन इकलाख भी अपने को बचा नहीं पाएंगे।

किशोर ने पांच वर्षीय मासूम से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

चौबेपुर, बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शाम मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। गांव के ही 14 वर्षीय किशोर ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पीड़िता के पिता ने बताया कि वह किसी काम से चौबेपुर गए थे और पत्नी पड़ोसी के घर पर थी। इस दौरान घर में अकेली उनकी बेटी के साथ किशोर ने घिनौनी हरकत की। मां के लौटने पर बच्ची रोती मिली। पूछताछ में मासूम ने पूरी बात बताई तो परिजन सन्न रह गए।

सूचना मिलते ही चौबेपुर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और महिला शक्ति प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। प्रभारी निरीक्षक आशीष चौबे ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बिना अनुमति पाठशाला लगाने पर सपा नेत्री पर कसा शिकंजा

- विद्यालय बंद होने की अफवाह से मची थी हलचल।
- बीईओ बिल्हौर ने दर्ज कराया था मुकदमा।
- जांच पूरी कर पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने और बिना अनुमति सरकारी विद्यालय के बाहर बच्चों को पढ़ाने के मामले में समाजवादी पार्टी की नेत्री रचना सिंह गौतम अब कानूनी घेरे में आ गई हैं। अरौल पुलिस ने भी बीईओ की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रकरण जुलाई माह का है, जब सपा नेत्री ने शाहमपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बाहर पीडीए पाठशाला के नाम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इस दौरान विद्यालय बंद होने की बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिससे विभागीय छवि पर असर पड़ा।

बीईओ रवी कुमार सिंह के अनुसार विद्यालय न तो बंद था और न ही पेयरिंग सूची में शामिल था। बिना अनुमति इस तरह की गतिविधि न केवल शिक्षा विभाग की साख को प्रभावित करती है, बल्कि यह बच्चों की सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर मामला है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सपा नेत्री रचना गौतम पर दो धाराओं में चार्जशीट दायर की गई है। आजकल यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है।

झूठे मुकदमे झूठी चार्जशीट हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। तुम जेल भेजो हम जाने को तैयार हैं जब भी छूटेंगे। सरकार की आंखों में आंख डालकर शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। क्योंकि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और सावित्रीबाई फुले जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं।

– रचना सिंह गौतम
पूर्व विधायक प्रत्यासी
बिल्हौर विधानसभा

सम्पादकीय

सतर्कता से टिकेगा इस्राइल-हमास युद्धविराम

अब भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दंभी तेवरों की तर्ज पर लाख दावे करते रहें कि गाजा युद्ध समाप्त हो गया है। मगर हकीकत है कि एक छोटी सी चिंगारी भी युद्ध को भड़का सकती है। एक हकीकत है कि दो साल से जारी युद्ध में जहां एक ओर भले ही गाजा पूरा तबाह हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद हमास के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। उनके पास ट्रंप के भारी दबाव व परिस्थितियों के चलते शांति समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। वहीं दो साल तक युद्ध लड़ते-लड़ते इस्राइली सेना में भी थकान देखी गई थी, साथ ही आतंरिक दबाव युद्ध रोकने के लिये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी बराबर बना हुआ था। ट्रंप के बड़बोले दावों को पश्चिमी एशिया और शेष दुनिया बेशक गंभीरता से न लेती रही हो, लेकिन अब एक हकीकत सामने है कि उनके हस्तक्षेप ने गाजा में फिलहाल तोपों को शांत किया है। डोनाल्ड ट्रंप का सोमवार को इस्राइल में एक नायक जैसा स्वागत किया गया। अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने आखिरकार शेष जीवित बचे बीस इस्राइली बंधकों को रिहा कर दिया। जिसके बाद इस्राइल में किसी बड़े उत्सव जैसा जश्न दिखा। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्राइल-हमास युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में, बहुत संभव है कुछ हफ्तों में हो। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर प्रयास लगातार होते रहें। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती भूतहा खण्डहर में तब्दील हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण की होगी। दो साल से लगातार जारी युद्ध के चलते यह इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। कहना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में इस्राइल की निरंकुशता पर किसी हद तक अंकुश लग पाता है, ताकि गाजा के लोग फिर से सामान्य जीवन की कोशिश में किसी हद तक सफल हो सकें।दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस्राइल और हमास के संघर्ष ने करीब बाइस लाख से अधिक लोगों को बेघर करके भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिये समझौते के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करना बेहद जरूरी होगा।

जिसमें बंधकों व कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को अनवरत जारी रखना और इस्राइली सेनाओं की गाजा के मुख्य शहरों से आंशिक वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसके बाद ही दूसरे चरण की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बेहद मुश्किल चुनौतियों वाला चरण होगा। इस दौरान कई संवेदनशील मुद्दे सामने होंगे। सवाल यह भी रहेगा कि लड़ाई खत्म होना एक स्थायी प्रक्रिया बन सकेगी। युद्ध समाप्ति के बाद घनी आबादी वाले इलाके में शासन कैसे चलेगा? क्या समझौते के अनुरूप हमास की भूमिका प्रशासन में खत्म हो जाएगी? क्या वास्तव में हमास हथियार डाल देगा? हालांकि, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस्राइली संसद में ट्रंप ने दावा किया है कि हमास उनकी निशस्त्रीकरण योजना के प्रावधानों का पालन करेगा। लेकिन इस चरमपंथी समूह ने फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा मिलने से पहले इस संभावना से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करने वाले हैं, जो गाजा के शासन के लिये एक अस्थायी गैर-राजनीतिक समिति के कामकाज की देखरेख करेगा। निस्संदेह, इस भावनात्मक मुद्दे को राजनीतिक रूप से कुशलता पूर्वक संभालने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से इस विवाद के पटाक्षेप के लिये दो-राज्य समाधान के लिये स्पष्ट समय-सीमा का अभाव एक कसक के रूप में महसूस किया जाता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन देर-सवेर उन्हें अहसास हो सकता है कि उन्होंने इस बेहद जटिल मुद्दे के समाधान की कोशिशों में अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है।

तालिबान को सैन्य मदद की आशंका से सहमा पाक

ज्योति मल्होत्रा

बाहर देखने पर यह लग रहा है, कि अफ़ग़ानिस्तान-भारत के बीच आर्थिक और मानवीय सहयोग के हवाले से कूटनीति हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिकार इसकी पड़ताल में लगे हैं कि नई दिल्ली, काबुल को इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर...बाहर देखने पर यह लग रहा है, कि अफ़ग़ानिस्तान-भारत के बीच आर्थिक और मानवीय सहयोग के हवाले से कूटनीति हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिकार इसकी पड़ताल में लगे हैं कि नई दिल्ली, काबुल को इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर सैन्य साज़ो-सामान की मदद तो नहीं कर रहा है?पाक-अफ़ग़ान युद्ध ऐसे ही नहीं रुका है। उसका सबसे बड़ा कारण भारत रहा है। दावेदारी सऊदी अरब, यूएई और ईरान की तरफ़ से हो रही है कि उनके समझाने-बुझाने पर दोनों पक्ष मान गए हैं। इस तथाकथित शांति रथ के चौथे सवार, राष्ट्रपति ट्रम्प भी हो गए हैं। ट्रम्प ने बयान दिया,

'मैं तो शांति कराने में माहिर, 'पीस एक्सपर्ट' हूं। भारत-पाक को टैरिफ की धमकी दी, वो मान गए।' अब कोई पूछे, अफ़ग़ान अमीरात ट्रम्प की टैरिफ धमकी को गंभीरता से लेगा क्या? उनके पास खोने के लिए है क्या? ख़ैर, इस हंसी-मज़ाक़ से अलग, जो कुछ पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया ने अपने सत्ता प्रतिष्ठान को समझाया है, वो बिलकुल 'कन्विंसिंग' और निशाने पर था।भारत क्यों कारण रहा, इसे समझने के लिए पाकिस्तान से प्रकाशित दो अख़बारों के सम्पादकीय को पढ़ लेना काफी होगा। 'अफ़ग़ान क्लैशेज़ ' शीर्षक से द डॉन सम्पादकीय लिखता है, 'पाकिस्तान को इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि भारत और अफ़ग़ान तालिबान, जो कभी कट्टर दुश्मन थे, के बीच अचानक संबंधों में गर्मजोशी आ गई है, और हाल ही में अफ़ग़ान विदेशमंत्री का नई दिल्ली में सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया। इसलिए, काबुल के साथ संबंधों को, चाहे कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हों, और बिगड़ने देना इस देश के हित में नहीं होगा।''दिल्ली-काबुल पैचअप' शीर्षक से एक्सप्रेस ट्रिब्यून का सम्पादकीय है, 'चूंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति, चाहे वह भारत हो या अफगानिस्तान, शांति का हाथ बढ़ाया है। आपसी सम्मान और सौहार्द के आधार पर संबंध बनाने की कोशिश की है, इसलिए अब समय आ गया है कि कूटनीति को एक और मौका दिया जाए। अफगान तालिबान अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए, ताकि आतंकवाद से निपटने में सहयोग किया जा सके तथा संबंधों में शांति सुनिश्चित की जा सके।'भारत में मुत्ताक़ी के भव्य स्वागत को लेकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लोट रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का एक हिस्सा गुरुवार को काबुल में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान की बेवकूफ़ाना हरकत मान रहा है। डॉन ने लीपापोती करते हुए लिखा, 'फ़िलहाल, शत्रुता समाप्त हो गई है। और अब इस मामले को और बिगड़ने से रोकना चाहिए। हालांकि अतीत में छोटे स्तर की झड़पें हुई, लेकिन हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी झड़प है।'तालिबान शासन ने 85 पाकिस्तानी सैनिकों-अफसरों को ढेर किये जाने का दावा किया है। जबकि पाक सेना के जनरल केवल 23 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार कर रहे हैं। सबसे मुश्किल में सियासतदां फंसे हैं। 'खुद मियां फ़ज़ीहत' जनता को जवाब कैसे दें? राष्ट्रपति ज़रदारी ने 'भारत द्वारा प्रायोजित' आतंकवाद के खतरे को 'क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा' बताया। राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की हालिया 'उकसावे वाली कार्रवाइयों' की कड़ी निंदा की, और दोहराया कि पाकिस्तान राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा।दरअसल, इन्हें भारत का डर सताने लगा है कि इस बार डुरंड लाइन पर कोई 'ग्रेट गेम' दिल्ली की तरफ से न हो जाये। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,640 किमी लंबी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है।

यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलोचिस्तान से बीच से होकर गुजरती है। ये दोनों इलाके आतंकग्रस्त हैं, जहां कबीलाई क्षत्रपों की चलती है। पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट शहीद जावेद बुर्की कहते हैं, 'वाशिंगटन और इस्लामाबाद, दोनों ही इस्लामिक स्टेट-खोरासन और टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को नियंत्रण में लाने में काबुल की मदद चाहते हैं।

'अफ़ग़ानिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी अब भी अमेरिका ने कर रखी है। अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक के अरबों डॉलर की डिपॉज़िट पर अमेरिका जिस तरह कुंडली मारे बैठा है, उससे इस देश की बैंकिंग प्रणाली चरमरा रही है। अमेरिका की आंखें अफ़ग़ान ज़मीन के नीचे छिपे दुर्लभ खनिजों पर गड़ी हैं।

बेहतर इंटरनेट पहुंच से ग्रामीण विकास की राह

ग्रामीण भारत

चरणदास निरंजन

ग्रामीण भारत की तेज गति से प्रगति के लिए हरेक व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच और हर गांव तक हाईस्पीड डेटा सुलभ होना जरूरी है। बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी व डेसिटी से ही गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, जो समावेशी विकास की नींव है।भारत की विकास गाथा तब तक अधूरी है जब तक इसकी असली ताक़त 'ग्रामीण भारत' डिजिटल हाइवे से पूरी तरह नहीं जुड़ती। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन सुलभ इंटरनेट की पहुंच से अब भी दूर है।

शहरी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और शासन में डिजिटल क्रांति स्पष्ट दिखती है, जबकि गांव आज भी कमज़ोर नेटवर्क और सीमित डिजिटल साक्षरता से जूझ रहे हैं।

इस खाई को पाटना ही आने वाले दशक में समावेशी विकास और असमानता दूर करने का निर्णायक कारक बनेगा।यह सच है कि मौजूदा सरकार ने डिजिटल भारत अभियान को केवल शहरों तक सीमित न रखकर उसे गांवों-कस्बों तक पहुंचाने की दिशा में कई कदम उठाए। डिजिटल इंडिया दृष्टि ने तकनीक को विलासिता से सशक्तीकरण के औज़ार में बदल दिया है। आज किसान ऑनलाइन मंडी भाव देख रहे हैं, महिलाएं सीधे लाभ हस्तांतरण योजनाओं से जुड़ रही हैं, विद्यार्थी ई-लर्निंग तक पहुंच रहे हैं और रेहड़ी वाले तक क्यूआर कोड से नकद रहित भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। यह केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक क्रांति का प्रतीक है, जो गांवों में अवसरों का विस्तार कर रही है।गांवों की ज़िंदगी में डिजिटल क्रांति से ऑनलाइन पढ़ाई और रोज़गार के कारण शहरों की ओर पलायन में कमी आ रही है। वहीं, इंटरनेट से महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म ऋण और ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिये आर्थिक आत्मनिर्भर बन रही हैं। विश्व बैंक के अनुसार, इंटरनेट तक पहुंच रखने वाली ग्रामीण महिलाओं को 15 प्रतिशत अधिक रोज़गार अवसर मिलते हैं। साथ ही, नेटवर्क के ज़रिए गांव अब राष्ट्रीय विमर्श में भाग ले रहे हैं।

अपनी सांस्कृतिक विरासत का डिजिटल संरक्षण भी कर पा रहे हैं।गौरतलब है कि भारतनेट परियोजना के तीसरे चरण पर 1.39

लाख करोड़ रुपये (2023-25) खर्च किए जा रहे हैं। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 2026 तक 90 प्रतिशत आबादी को 5जी से जोड़ने का दावा कर रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक विकल्प है, लेकिन इसकी लागत 1,200-1,500 रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। हालांकि तथ्य यह भी कि भारत हर साल 6.4 लाख करोड़ रु. ग्रामीण विकास पर खर्च करता है।

यदि इसका 10 फीसदी भी डिजिटल नेटवर्क विस्तार पर लगाया जाए, तो इससे हर गांव जुड़ सकता है।सवाल उठता है कि गांवों तक नेटवर्क पहुंचना क्यों ज़रूरी है? इसके उत्तर कई हैं। एक तो ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लर्निंग एप्स ग्रामीण छात्रों के लिए वरदान हैं। यूनिसेफ़ के अनुसार, इससे गांवों में बच्चों की सीखने की क्षमता 20-25 प्रतिशत बेहतर रही है। इस समय ग्रामीण भारत की 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम की है। डिजिटल नेटवर्क से उन्हें स्किल ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्स और रिमोट जॉब्स के अवसर मिल सकते हैं।वहीं इंटरनेट सुविधा के चलते कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है। नीति आयोग के अनुसार, किसान मौसम, फसल मूल्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर 8-10 प्रतिशत अधिक आय अर्जित कर रहे हैं।यही नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां ग्रामीण इलाकों में प्रति 10,000 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है, ऐसे में 'ई-संजीवनी' जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म ने अब तक दो करोड़ से अधिक परामर्श प्रदान किए हैं। इंटरनेट के माध्यम से सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) से पेंशन, मज़दूरी और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और शासन में पारदर्शिता बढ़ी है।पिछले दशक में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद ट्राई के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 52 प्रतिशत ग्रामीण घरों में इंटरनेट की पहुंच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 95 प्रतिशत है। भारतनेट के तहत 6.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

अभी तक 60 प्रतिशत से कम गांवों में ही कार्यशील हाई-स्पीड नेटवर्क पहुंच पाया है। यह भी कि भारत अब कनेक्टिविटी बढ़ाने की दौड़ में विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहा। बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी स्टैक पहल ऐतिहासिक उपलब्धि है। सी-डॉट, तेजस नेटवर्क और टीसीएस के सहयोग से विकसित यह तकनीक महज़ 22 महीनों में तैयार हुई। भारत अब उन पांच देशों में शामिल हो गया है जो यह क्षमता रखते हैं।वहीं, बीएसएनएल अब तक 92,000 साइटें स्थापित कर चुका है, जिससे 2.2 करोड़ से अधिक लोग—जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण उपभोक्ताओं की है—इंटरनेट से जुड़े हैं। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जीवंत मिसाल भी है। यही नहीं, स्वदेशी स्टैक से स्थानीय रोज़गार, सप्लाई चेन और तकनीकी कौशल का विकास हुआ है। यह तकनीक निर्यात योग्य भी है, जिससे भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि टेलीकॉम उत्पादक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।

इस सबके बावजूद अब भी चुनौतियां शेष हैं। सस्ता डेटा होने पर भी स्मार्टफ़ोन और मासिक खर्च गरीब परिवारों पर बोझ हैं। दूसरी ओर, 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण वयस्क अब भी डिजिटल ज्ञान से वंचित हैं।

ऑयल टैंकर ट्रेन से फिर शुरू हुआ डीजल चोरी का धंधा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

» सोमवार रात गिरोह के कुछ सदस्यों को आरपीएफ ने दौड़या लेकिन वे पकड़ नहीं सके

कानपुर। तेल वाहक मालगाडियों से डीजल चोरी करने वाला गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कुछ ही दिन पहले शिवली थाने से जेल भेजा गया कुख्यात सरगना देशराज अब जेल से छूटने के बाद दोबारा पुराने पेशे में लौट आया है। सूत्रों के अनुसार, उसने अब तेल चोरी के लिए कुख्यात सौरभ पहाड़िया गैंग के साथ हाथ मिला लिया है।इस गैंग के तार पनकी, सचेंडी, भाऊपुर और मैथा तक फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक किनारे खड़ी तेल वाहक मालगाडियों से पाइप और मोटर पंप के जरिए डीजल चोरी करते हैं।

सूत्रों का दावा है कि इस पूरे अवैध कारोबार को आरपीएफ के कुछ भ्रष्ट कर्मियों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी मदद से गैंग को ट्रेन मूवमेंट और पेट्रोलियम वैगनों की लोकेशन की जानकारी पहले से मिल जाती है। जानकारी में आया है कि सोमवार देर रात इस गिरोह के कुछ सदस्यों को ट्रेन से डीजल चोरी करते समय आरपीएफ टीम ने दौड़या लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके।

चोरी का डीजल टिकरा में बिकता

ट्रेन टैंकर से चोरी किए गए डीजल को कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में सक्रिय डीजल कारोबारियों को बेचा जाता है। वहीं से यह तेल आगे छोटे ट्रांसपोर्टरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इस नेटवर्क में देशराज और सौरभ पहाड़िया के साथ विकास गौतम, लालू गौतम और मुन्ना नाम के युवक भी सक्रिय बताए जा रहे हैं।दैनिक स्वराज इंडिया ने पहले भी इस गोरखधंधे का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। हालांकि जेल से छूटने के बाद अब वही पुराना नेटवर्क फिर से जीवित होता दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे गिरोह पर बड़ी कार्रवाई संभव है।

देशराज

सौरभ पहाड़िया

मुन्ना

विकास गौतम

लालू गौतम

» हाल में ही जेल से छूटे देशराज ने सौरभ पहाड़िया गैंग के साथ मिलाया हाथ

» कुछ आरपीएफ कर्मियों की मिलीभगत से पनकी से मैथा तक सक्रिय नेटवर्क

यह सभी गिरोह के सदस्य हैं, जो पहले भी जेल जा चुके

चाभी बनाने के बहाने घर में चोरी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

» त्रिनेत्र ऐप से 100 कैमरों की जांच कर पुलिस ने सुलझाई वारदात

» फजलगंज स्थित होटल से सभी जेवर बरामद, दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के निवासी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जो चाभी बनाने के बहाने घरों में प्रवेश कर कीमती जेवरात चोरी करते थे।आनंदबाग क्षेत्र में हुई इस वारदात का खुलासा पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप की मदद से लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फजलगंज से गिरफ्तार कर लिया और चोरी गए सभी जेवरात बरामद कर लिए हैं।

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी

पीड़िता कुसुमा देवी राठौर निवासी आनंदबाग ने पुलिस को बताया कि दो चाभी बनाने वाले युवक उनके घर अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने आए थे। मौका मिलते ही उन्होंने बहू की अलमारी के लॉकर में रखे सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप से मिले फुटेज का विश्लेषण किया और अभियुक्तों की लोकेशन फजलगंज क्षेत्र में पाई। चौकी प्रभारी नितिन कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को फजलगंज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम सिकंदर सिंह चावला और सतनाम सिंह निवासी ग्राम बयडीपुरा बाग, थाना बाघ, जिला धार (मध्यप्रदेश) बताया। उनकी निशानदेही पर खंजन होटल फजलगंज से चोरी गए सभी सोने-चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए।

सुलगती बीड़ी की आग से बुजुर्ग की जलकर मौत

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बिधनू थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात कठारा गांव में एक हृदयविदारक घटना हुई। यहां बिस्तर पर सुलगती बीड़ी से लगी आग में चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग जिंदा जल गए। पड़ोसियों के अनुसार बुजुर्ग के चीखने पर वह लोग दौड़े, लेकिन आग की विकराल लपटों के सामने घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। करीब एक घंटे बाद आग बुझाकर ग्रामीण घर के अंदर पहुंचे, तो बुजुर्ग का जला शव पड़ा मिला।जानकारी पर बिधनू पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जांच की। इसके बाद शव पोस्टमार्टम भेज दिया। उक्त गांव निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि उनके पिता गंगाप्रसाद (90) किसान थे। तकरीबन एक साल से सांस व घुटनों की बीमारी से परेशान होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि वह पांच भाई सुरेंद्र, वीरेंद्र, सत्येंद्र व रवि है। सब भाई अपने-अपने परिवार के साथ घर से कुछ दूरी पर रहते हैं।

बताया कि मां शिवरानी की 10 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता अकेले रहते थे। बताया कि पिता बीड़ी पीते थे, सोमवार देर रात बीड़ी पीने के बाद वह सो गए। इसके बाद सुलगती बीड़ी ने बिस्तर में आग पकड़ ली। कुछ देर बाद लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। पिता बिस्तर पर छटपटाते रहे, आग की ऊंची लपटें उठती देख पड़ोसी मुंशीलाल ने अरविंद को सूचना दी। बताया की आपके कारण गृहस्थी का अन्य सामान भी पूरी तरह से जल गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कानपुर की लाइफलाइन जीटी रोड फिर चमकेगी

13 करोड़ की लागत से शुरू हुआ सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य, बारिश के बाद खराब जीटी रोड से चलना था मुश्किल, मिलेगी राहत

अनूप अवस्थी
» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।शहर की धड़कन कही जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड (जीटी रोड) अब एक बार फिर चमकने जा रही है। बारिश के बाद जीटी रोड की जर्जर हालत से जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब शासन से 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद सड़क के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया है।

जानकारी के अनुसार, लखनऊ की एमडीडी निर्माण संस्था को इस परियोजना का कार्यभार सौंपा गया है। संस्था ने निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। क्क्ष्ष (एनएच) के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जयंत ने बताया कि जीटी रोड पर आईआईटी कानपुर से लेकर रामदेवी चौराहा तक डामरीकरण, साइड ड्रेनेज सुधार, डिवाइडर रिपेयर और रिफ्लेक्टर मार्किंग का काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सड़क टिकाऊ और सुरक्षित बन सके। ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पहले अधिक से अधिक हिस्सा तैयार कर लिया जाए, जिससे त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू रहे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण संस्था आगामी 5 वर्षों तक सड़क का मेंटेनेंस भी देखेगी, जिससे भविष्य में सड़क की स्थिति बेहतर बनी रहे।

जीटी रोड कानपुर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जहां से रोजाना करीब 60 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही होती है, जिससे सड़क पर दबाव और भी बढ़ जाता है। ऐसे में सड़क की मरम्मत से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जीटी रोड की मरम्मत से न सिर्फ यात्रा में राहत मिलेगी, बल्कि शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी नया जीवन मिलेगा।

कानपुर के विकास और यातायात के दृष्टिकोण से यह परियोजना एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो शहर की रफ्तार को फिर से नई दिशा देगी।

जीटी रोड एक नजर में....

- 13 करोड़ की लागत से जीटी रोड का पुनर्निर्माण शुरू
- लखनऊ की एमडीडी निर्माण संस्था कर रही कार्य
- IIT कानपुर से रामदेवी तक सड़क होगी दुरुस्त
- दीपावली तक पूरा होगा अधिकांश कार्य
- 5 साल तक सड़क का रखरखाव करेगी निर्माण इकाई रोजाना 60 हजार से अधिक हन करते हैं आवागमन

थार खरीदने के लिए की बुकिंग, रुपया हड़प गया शोरूम कर्मी

» शोरूम मालिक व मैनेजर पर दो लाख हड़पने का आरोप, मुकदमा दर्ज

»कर्मचारी पर कई ग्राहकों से फर्जीवाड़े का आरोप, कंपनी ने कहा—निकाल दिया गया है युवक

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। रायपुरवा थानाक्षेत्र में कार बुकिंग के नाम पर दो लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शोरूम मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।झकरकटी निवासी अनिकेत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने दो जुलाई को आचार्य नगर स्थित एक कार शोरूम में थार गाड़ी देखी और बुकिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। शोरूम कर्मचारियों ने पहले 21,000 रुपये जमा करने पर बुकिंग की बात कही। अगले दिन टेस्ट ड्राइव के दौरान कर्मचारी ने बताया कि अगर वे गाड़ी की डिलीवरी 1 नवंबर को चाहते हैं तो दो लाख रुपये काउंटर पर जमा करने होंगे।

अनिकेत के अनुसार, उन्होंने काउंटर पर दो लाख रुपये जमा किए और रसीद ले ली। लेकिन जब वे 29 सितंबर को गाड़ी की स्थिति जानने शोरूम पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि कोई रकम जमा नहीं हुई है और दी गई रसीद नकली है इस पर उन्होंने रायपुरवा थाने में शोरूम मालिक मनीष गुप्ता और मैनेजर शैलेंद्र मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।थाना प्रभारी विजय सरोज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं, शोरूम मैनेजर शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि उनके यहां काम करने वाला कर्मचारी आसिफ आलम कई ग्राहकों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। उसे डेढ़ महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, और कंपनी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

खाद की किल्लत से किसान परेशान दिनभर लाइन लगने के बाद भी खाली हाथ

» किसानों ने कहा समय से खाद नहीं मिलने से फसलें हो रही बर्बाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डीएपी खाद के लिए समितियां में मारामारी है। किसान केंद्र में सुबह से ही पहुंच जाते हैं लेकिन केंद्र 12 बजे खुल रहे हैं। जिसके चलते किसानों को समय से खाद नहीं मिल रही तो फसलें बर्बाद हो रही हैं। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत साधन सहकारी समिति सलेमपुर महेरा जो की भवनपुर में स्थित है। वहां डीएपी खाद के लिए मारामारी है । यहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि समिति समय से नहीं खुलती जिसके चलते भीड़ बढ़ती जाती है। समिति में 7 ग्राम पंचायत के लोग खाद लेने के लिए आते हैं।

मंगलवार को तो समिति का ताला दोपहर 12 बजे खुला। लोगों ने जिला कृषि अधिकारी से शिकायत करने की बात कही। खाद लेने के लिए आए किसान श्याम वीर निवासी भीमसेन पुरवा, रामनगर निवासी विजय कुमार,भीमसेन पुरवा निवासी रामनरेश, माखन पुरवा निवासी भारत सिंह, रामनगर निवासी राजू,ताजपुर निवासी सुनील ने बताया कि वे खाद के लिए दो दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को तो उन्हें 3 घंटे कतार में खड़ा होना पड़ा। शिकायत जब पुलिस से की गई तो कहीं जाकर 12 बजे समिति का ताला खुला और खाद वितरण शुरू हुआ। किसानों ने बताया कि धान काली पी जा रही है। बारिश के बाद उसे डीएपी खाद की जरूरत है लेकिन समय से खाद न मिलने के चलते उनकी फसल बर्बाद हो रही है। उन्होंने जिम्मेदारों से इस ओर ठोस कदम उठाने की मांग की। समिति के अध्यक्ष रामबाबू ने बताया कि 7 ग्राम पंचायत के करीब 50 मजरे इस समिति से लाभान्वित है। कल 300 बोरी खाद आई थी जो की बांट दी गई। किसान अधिक है खाद कम है। जिसके चलते दिक्कत आ रही है। पुलिस का सहयोग लेकर खाद वितरण किया जा रहा है।

क्या बोले उपजिलाधिकारी

एसडीएम सर्वेश सिंह ने बताया कि लेखपाल और फोर्स को भेजकर वितरण कराया जा रहा है। कृषि विभाग को पत्र भी लिखेंगे। अब नियमित समय से खाद वितरित की जाएगी।

» खाद के लिए लगी किसानों की लंबी लाइन

परिवहन विभाग की कार्रवाई पर टेंपो चालकों ने किया चक्का जाम

» गलत चालान के विरोध में भोगनीपुर के टेंपो चालक हड़ताल पर, यात्री परेशान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। भोगनीपुर से मूसानगर-घाटमपुर मार्ग पर टेंपो चालकों ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की कार्यवाही के विरोध में चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि विभागीय टीम ने बिना कारण कई प्राइवेट वाहनों को सीज कर दिया और 30,000 रुपये तक का चालान थमा दिया। इससे गुस्साए टेंपो चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। भोगनीपुर, मूसानगर और घाटमपुर रूट पर रोजाना सैकड़ों यात्री टेंपो से सफर करते हैं क्योंकि यहां रोडवेज बसों की संख्या बहुत कम है। हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई यात्री भोगनीपुर से हल्दरपुर रेलवे क्रॉसिंग तक पैदल चलने या ट्रैक के रास्ते जाने को मजबूर हैं। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है।टेंपो चालकों कमल कुमार, धर्मेंद्र, शिवम, कोमल गुप्ता, लल्लन, रमेश गुप्ता, सर्विस सोनू और विनीत पांडे ने बताया कि परिवहन विभाग की कार्रवाई मनमानी है। उन्होंने जिलाधिकारी कानपुर देहात कपिल सिंह को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। डीएम कपिल सिंह ने बताया कि उप जिलाधिकारी भोगनीपुर देवेंद्र सिंह और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। स्थिति का जायजा लेकर जल्द समाधान कराया जाएगा।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को दिया सशक्तिकरण का संदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्राम पंचायत गजनेर में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान अनीशा बेगम ने की। यहां महिला पुलिस टीम, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं ब्लॉक स्तर के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

» महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

» अधिकारियों ने कहा महिला सशक्तिकरण ही समाज की असली प्रगति

कार्यक्रम में महिला पुलिस टीम ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी कानूनी जानकारी, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, तथा महिला हेल्पलाइन सेवाओं (1090, 181, 112) के बारे में विस्तार से बताया। खंड विकास अधिकारी विमल सचान ने कहा महिलाओं का आत्मनिर्भर और शिक्षित होना ही समाज की सच्ची प्रगति का प्रतीक है। वहीं, लेखपाल रामाकांत श्रीवास्तव, मिशन शक्ति प्रभारी रेनू, ब्लॉक समन्वयक आशीष मिश्रा, और कृषि विभाग के मुकेश कुमार ने राजस्व योजनाओं, महिला कल्याण कार्यक्रमों, पोषण एवं कृषि आधारित आजीविका पर जानकारी साझा की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आयुष्मान भारत कार्ड, संचारी रोग नियंत्रण, और नशा मुक्ति अभियान की विस्तृत जानकारी दी।बैठक में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मो. फिरोज, ग्राम पंचायत सहायक नफीस अली, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ गीता देवी, गुड़िया मिश्रा, शैल तिवारी, सारिका सिंह, आशा कार्यकर्त्रियाँ संतोषी देवी, उपासना देवी, और समूह सखियाँ लता देवी, उर्मिला देवी, चांदनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

सीएम ग्रिड योजना-सीवर में डाली गई पेयजल पाईप लाईन

मनमाने निर्माण पर भड़का लोगों का गुस्सा

पंकज कुमार सिंह
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

- आवास विकास बगिया क्रासिंग रोड से केसा चौराहा तक सीएम ग्रिड योजना के तहत 1021 लाख के बजट सै चल रहा निर्माण कार्य
- चैंबर ऐसा बना रहे की सडक का उठान होगा ऊंचा मकान हो जाएंगे दो फीट गहरे
- आईजीआरएस के तहत सीएम की चौखट तक लगाई हैं सात बार गुहार पर एक न सुनी गई
- डेड लाईन पूरी पर 100 मीटर भी नहीं हुआ काम, 1.150 किमी होना है निर्माण

कानपुर। सीएम ग्रिड परियोजना के तहत निर्माण कार्य बगिया रोड निवासियों के लिए नरक का सबब बन हुआ है। आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स से लेकर केसा चौराहे तक डबल रोड पिछले दो सालों से खत्म हो चुकी है। सीएम ग्रिड योजना के तहत लोगों में यहां परसे नरक से उबरने की उम्मीद जगी लेकिन निर्माण ऐसेन्सियों की मनमानी और सरकारी हुक्मरानों की अनदेखी ने लोंगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कानपुर नगर निगम इस परियोजना की कार्यदायी संस्था है। मेसरूस डेल्टा इरेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड इस परियोजना का कॉन्ट्रेक्टर है।

मंगलवार को यहां स्थानीय निवासियों गुस्सा भडक गया। लोग सडकों पर उतर आए। यहां लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए मीडिया वार्ता में बताया कि यहां निर्माण कार्य यहां मनमर्जी से चल रहा है। सीवर में पेयजल आपूर्ती की पाईप लाईन डाल दी गई है। यदि पेयजन लाईन लीकेज हुई तो सीवर घरों में सप्लाई होगा और लोगों की जिन्दगियां खतरे में पडेगी। सीवर चैंबर इतने ऊंचे किए गए हैं कि भविष्य में सीवर ओवरफ्लो हुआ तो घरों में गंदगी भर जाएगी। निर्माण काराय ऐसा है कि सडक का उठान आवास विकास फाउंडेशन से दो फीट ऊपर जा रहा है। इससे करोंडों की कीमत के घर जमीन में धंस जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित लाल वर्मा अतिश पटेलशिवम आनन्द राजपूत ने बताया कि वर्तमान में सीवर चैंबर के बने गड्ढों में राहगीरों के सुरक्षा इंतजाम नदारद हैं। रातबिरात में लोग गिरकर चोटिल होते हैं। सीवर का भराव इतना है कि बडे बडे गड्ढों में पानी

की सडन और जलभराव से मच्छर पनप रहे हैं।लेकिन किसी को यहां के निवासियों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। मौके पर अनूप गौर, राजाराम, विकी भटनागर, पुष्पेश राजपूत, प्रकाश सिंह, आरए गौतम, आशीष विश्नोई, आशीष कुशवाहा, गोविन्द पाल, रमाकान्त कटियार, सीबी सचान, अशोक खरे, इंदू प्रकाश तिवारी, अखिलेश आदि रहे।

एक ही रोड पर मनमाने मानक के तहत निर्माण

स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य में खामियों को उजागर करते हुए बताया कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स आवास विकास से लेकर मकान संख्या 13 तक सीवर लाईन के चेम्बर बेमानक व ईंटों से बनाए गए हैं और इनके निर्माण में मसाला अधोमानक लगाया गया है। जबकि केसा चौराहे से महाराणा प्रताप स्कूल तक आसीसी के तहत कंक्रीट से

निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में मनमाना निर्माण कार्यदायी संस्था व निर्माण ऐजेंसियों पर सवाल खडे कर रहा है।

आईजीआरएस से 7 बार शिकायत सीएम को भेजी गईं

बताया गया कि निर्माण कार्य में मनमर्जी और यहां की बदहाली को लेकर आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री को आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत भेजी गई हैं। विगत फरवरी मास से कुल 7 आईजीआरएस दाखिल की गईं हैं आरोप है कि अफसरों ने गलत रिपोर्ट भेजकर सभी शिकायतों पर पानी नहीं सीवर डाल दिया है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि काम बन्द कराने को देकर फोन आते हैं लेकिन मनमानी नहीं रुक रही।

कलश यात्रा के साथ 19 से शुरू होगा श्रीविष्णु महायज्ञ

कामदगिरि पीठाधीश्वर स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी करेंगे प्रवचन, 27 नवंबर को होगा भंडारा

बैठक करते समिति के पदाधिकारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रनिया कस्बे में धार्मिक आस्था और भक्ति का माहौल एक बार फिर गूंजने वाला है। सनातन धर्म प्रचार समिति रनिया द्वारा आयोजित 19वें श्रीविष्णु महायज्ञ, श्रीमद्भागवत, मानस एवं संगीत सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार की शाम एक प्रतिष्ठान पर समिति की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।

बैठक में निर्णय हुआ कि 19 नवंबर को भूमि पूजन और भव्य कलश शोभायात्रा के साथ अनुष्ठान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर से कथा आरंभ होगी, जो 26 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। अंतिम दिन 27 नवंबर को विशाल भंडारे के आयोजन के साथ महायज्ञ का समापन होगा।कार्यक्रम में कामदगिरि पीठाधीश्वर स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज अपने मुखारविंद से भागवत कथा का अमृतपान कराएंगे। साथ ही प्रसिद्ध भजन गायक भक्ति रस से वातावरण को संगीतमय बनाएंगे।बैठक में समिति के प्रबंधक पप्पू शर्मा और संयोजक सोनू गुप्ता ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सेठ रामचरण के परिसर, रनिया बाजार रोड पर यह आयोजन संपन्न होगा। इस अवसर पर सुरेश त्रिपाठी, विष्णु कुमार गुप्ता, भोले शुक्ला, दयाशंकर गुप्ता, संजय गुप्ता, अनिल शर्मा, जीतू यादव, विमल तिवारी, अनिल सोनी, रोशन शर्मा, अरुण शर्मा आदि उपस्थित रहे।

अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा भारतीय संस्कृति का अनोखा संगम

दीपोत्सव 2025: अयोध्या के दीपक की ज्योति धर्म, राष्ट्र और विकास की त्रिवेणी

» रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव रामायण से योगी तक, परंपरा और प्रगति का अद्भुत समागम बना

» दीपों में ही नहीं, झांकियों में भी दिखाई देगी नवभारत केआत्मविश्वास और प्राचीन भारत की आत्मा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।त्रेता युग में जिस तरह कभी भगवान श्रीराम के वनवास से लौटने पर अयोध्या नगरी को दीपों की ज्योति से आलोकित किया गया था। वहीं आज उसी भूमि पर नवभारत के उज्ज्वल भविष्य की दीप्ति जगमगा उठी है। आज के दौर में अयोध्या में होने वाला यह दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक विकास के संगम का प्रतीक बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नौवें दीपोत्सव को 'नवभारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव' बनाने का संकल्प लिया है। सूचना विभाग और पर्यटन संस्कृति विभाग मिलकर इस आयोजन को भव्यतम स्वरूप देने की तैयारी में जुटे हैं।

जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी के अनुसार, इस बार सूचना विभाग द्वारा 15 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी जो योगी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएंगी। इन झांकियों में प्रदेश में हुए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के कार्यों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक झांकी एक कहानी कहेगी कैसे 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र ने प्रदेश को नई दिशा दी। कैसे परंपरा और प्रौद्योगिकी साथ-साथ चलकर 'नए उत्तर प्रदेश' की परिकल्पना को साकार कर रही हैं।

रामायण के सभी सात कांड का जीवंत चित्रण

पर्यटन संस्कृति विभाग इस दीपोत्सव में रामायण के सभी सात कांड बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड पर आधारित झांकियां प्रस्तुत करेगा। इन झांकियों में केवल घटनाएं नहीं, बल्कि रामायण की शिक्षाएं, आदर्श और संस्कार जीवंत रूप में दिखाए जाएंगे। भगवान श्रीराम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक नीति दर्शन है यह संदेश झांकियों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचेगा।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का उत्सव

इस बार दीपोत्सव केवल अयोध्या का नहीं, पूरे भारत का उत्सव बनेगा। हरियाणा का फाग, केरल का कथककली, राजस्थान का झूमर, पंजाब का भांगड़ा, ओडिशा का संबलपुरी नृत्य, गाजीपुर की डिबिया कला, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश की लोक परंपराएं सभी रामपथ पर एक साथ नृत्य करती दिखाई देंगी। लगभग 500 से अधिक कलाकारों की भागीदारी इस आयोजन को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का उत्सव बना रही है।

हर दीपक राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक

योगी सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है अयोध्या केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। यहां हर दीप राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यहां हर झांकी उस यात्रा की कहानी है जो राम से शुरू होकर नए भारत तक पहुंचती है।अयोध्या का दीपोत्सव आज एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उत्सव बन गया है। यह वह भूमि है जहां धर्म और नीति, संस्कृति और समृद्धि, परंपरा और प्रगति एक साथ चल रहे हैं। इस दीपोत्सव में केवल घी के दीप नहीं जलेंगे भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी चेतना भी प्रदीप्त होगी।

इटावा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

» कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है

कुलदीप गुप्ता उर्फ संतू

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा/प्रयागराज।पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता संटू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को दो महीने में विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इस अवधि के दौरान कुलदीप गुप्ता संटू की गिरफ्तारी पर स्पष्ट रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि राजीव यादव की संदिग्ध मौत के मामले में कुलदीप गुप्ता संटू को पुलिस ने वांछित घोषित किया था। गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी इटावा ने ?25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इस प्रकरण में राजनीतिक रस्साकशी और प्रशासनिक दबाव के आरोप लगातार उठते रहे हैं।स्थानीय राजनीतिक गलियारों में यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ की भूमिका स्पष्ट झलकती है। एक ओर पुलिस दबाव में कार्रवाई करती दिखी, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है।

अब देखना यह होगा कि आने वाले दो महीनों में पुलिस की विवेचना किस दिशा में जाती है और क्या इस बीच कोई नया तथ्य सामने आता है या फिर यह मामला भी राजनीति की धूल में दबकर रह जाएगा।

..तो मुस्कान मिश्रा की 'मुस्कान' सपा की सियासत पर भारी पड़ गई!

हनुमानगढ़ी की चौखट से निकला सियासी तूफान

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के दरबार में मुस्कान मिश्रा ने झुककर आशीर्वाद लिया और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सियासत झुक गई! 13 अक्टूबर का यह रविवार अब सपा की राजनीतिक कैलेंडर में एक नया अध्याय बन गया है, जहां 'भक्ति' और 'नीति' की रेखा गड्डमड्ड हो गई।

गौरतलब हो कि मुस्कान मिश्रा, जो जुलाई में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव बनी थीं, रविवार को हनुमानगढ़ी पहुंचीं। मुस्कान ने महंत राजू दास से आशीर्वाद लिया वही राजू दास जिन्होंने कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। सूरज पांडेय नाम के युवक ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला और लिखा कि

राजू दास का आशीर्वाद, समाजवादी विचारधारा का अपमान! इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुस्कान मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। बता दे कि मुस्कान मिश्रा सपा की इंस्टाग्राम स्टार हैं।4,600 से अधिक पोस्ट, 6.68 लाख फॉलोअर हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सपा के अंदर डिजिटल फ्रंट पर भी घमासान मच गया। एक धड़ा बोला मुस्कान को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। दूसरा बोला राजू दास के आशीर्वाद की कीमत सपा की साख नहीं हो सकती।

मुलाकात की यह फोटो वायरल है

राजू दास और अखिलेश की पुरानी अदावत

यह विवाद सिर्फ एक फोटो का नहीं है पृष्ठभूमि में है वह जख्म जो राजू दास की टिप्पणी ने सपा को दिया था। कुंभ मेले में मुलायम सिंह की मूर्ति पर तंज कसते हुए राजू दास ने सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द लिखे थे। अखिलेश ने पलटवार किया था जैसी संगत, वैसी वाणी... कह गए सब संत-ज्ञानी। अब उसी संत से सपा की एक राष्ट्रीय पदाधिकारी की मुस्कुराती मुलाक़ात पार्टी के लिए वैचारिक झटका बन गई।

नशे के कारोबरियों की कमर तोड़ने का मिशन शुरू

अयोध्या पुलिस का 'ऑपरेशन गांजा क्रैक डाउन'

» एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में इनायतनगर पुलिस ने पकड़ा 22 लाख का गांजा

» उड़ीसा से चल रहा था नेटवर्क, जिले के कई शहरों में गांजा सप्लाई करते था पकड़ा गया तस्कर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या।अयोध्या पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मादक पदार्थों की तस्करी अब जिले की सरहद पार नहीं कर सकती। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 गौरव ग्रोवर के निर्देशन और एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के नेतृत्व में 'ऑपरेशन गांजा क्रैकडाउन' के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उड़ीसा से संचालित गांजा सप्लाई चैन की कड़ी को तोड़ दिया है। इस कड़ी में इनायतनगर थाना पुलिस ने गांव बंजरिया निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 91.953 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक यह बरामदगी एक होंडा सिटी कार (यूपी 44 बीआर 2961) से की गई,

जिसमें गांजा को 8 बोरियों में छिपाकर 88 पैकेटों में पैक किया गया था। कार से दो फर्जी नंबर प्लेट (डीएल 8 सीएल 7204), बिक्री से प्राप्त 9,050 नकद, दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर वाहन को सीज़ कर लिया। मिल्कीपुर के क्षेत्राधिकारी श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी सोनू कुमार उड़ीसा से आने वाले गांजे का भंडारण सुल्तानपुर-अयोध्या सीमा के बल्दीराय क्षेत्र में करता था। वहां से छोटे स्तर के तस्कर गांजा लेकर जिले के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक, यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और अब एसएसपी के निर्देशन में इसे तोडने की दिशा में निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी)/20/60 और आईपीसी की धारा 319(2)/318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरोह का सरगना अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिशें दे रही हैं।

कई बड़े चेहरे भी पुलिस के रडार पर

इस कार्रवाई की सराहना करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इनायतनगर थाना पुलिस टीम को बधाई दी और स्पष्ट कहा कि अयोध्या को नशे के कारोबार से पूरी तरह मुक्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। तस्करों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने भी कहा कि यह कार्रवाई पुलिस की प्रतिबद्धता का परिणाम है और अब ऐसे अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पूरे जनपद में लगातार छापेमारी अभियान चलेगा। पुलिस के रडार पर अब वे 'बड़े चेहरे' हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे धंधे को चला रहे हैं।

ग्रामीणों के जाल में फंस गया दहशत फैलाने वाला तेंदुआ

» तेंदुए के पकड़े जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या।कई महीनों से कैंट इलाके में दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार मंगलवार को पकड़ लिया गया। लेकिन दिलचस्प यह रहा कि ग्रामीणों द्वारा लगाया गया जाल था जिसमें यह खूंखार तेंदुआ फंस गया।

सूत्रों के अनुसार, सहादतगंज जंगल के पास ग्रामीणों ने पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए जाल बिछाया था। सुबह उसमें अचानक हरकत दिखी तो लोगों ने देखा कि तेंदुआ उसी में फँस चुका है। सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पंकज सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे और इलाके को घेर लिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुँचकर तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि यही वही तेंदुआ है, जिसने बीते महीनों से कैंट और डोगरा रेजीमेंट क्षेत्र में दहशत मचा रखी थी। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अब बच्चे बेखौफ बाहर खेलने लगे हैं और किसान फिर से खेतों की राह पकडने लगे हैं।

लाड़ली बहन योजना में 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सिफारिश पर बवाल

मोहन यादव की जातिवादी सोच से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल!

स्वराज इंडिया
अपना प्रदेश
10
27 प्रतिशत आरक्षण- 'महासंग्राम' की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश
»मोहन यादव की जातिगत राजनीति से मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज में गहराया आक्रोश
कई जगह चल रहे विरोध प्रदर्शन, भाजपा को हो सकता है नुकसान

» कार्यालय संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति एक बार फिर जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर उथल-पुथल में है। जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने लाड़ली बहन योजना में पचास प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की पैरवी की है। यह सिफ़ारिश डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (बी.आर.ए.यू.एस.एस.) की उस रिपोर्ट में की गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 2023 में तैयार करवाया था।

रिपोर्ट में न केवल पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई है, बल्कि यह भी सिफ़ारिश की गई है कि पिछड़े वर्ग में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर यानी सम्पन्न वर्ग की पहचान न की जाए, अर्थात आरक्षण पूरी तरह जातिगत आधार पर दिया जाए। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस कदम को जातिवादी तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया जा रहा है।

» सीएम की नीतियों पर सवर्ण समाज का गुस्सा चरम पर!

राज्यभर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की जातिवादी मानसिकता को लेकर जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। विरोधी दलों का कहना है कि मोहन यादव समाज को जाति के आधार पर बांटने का कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। विशेष रूप से सवर्ण समाज में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। भाजपा के पारम्परिक समर्थक वर्गों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को गंभीर हानि उठानी पड़ सकती है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बाँटने की नीति पर चल रहे हैं। जनता अब ऐसे जातिवादी रवैये से ऊब चुकी है और आने वाले समय में इसका उत्तर चुनाव में दे सकती है। क्रीमीलेयर की पहचान आर्थिक आधार पर एक लीडिंग अखबार के मुताबिक मोहन यादव सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की पहचान के लिए आर्थिक आधार नहीं लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना है, न कि केवल आय के आधार पर लाभ देना। वर्तमान नियमों के अनुसार, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें क्रीमीलेयर माना जाता है। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ओबीसी को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा।

यह रिपोर्ट महू स्थित बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने तैयार की थी। वर्ष 2023 में प्रदेशभर के 10,548 ओबीसी लोगों का सर्वे किया गया। सर्वे में साक्षात्कार, प्रश्नावली और गूगल फॉर्म के माध्यम से जानकारी जुटाई गई।

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 अक्टूबर को 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से भेज दिए हैं। श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 98.87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। हालांकि महिलाओं के खाते में अभी 1150 रुपये ही भेजे गए हैं। जल्द ही भाई दूज के शगुन के तौर पर 250 रुपये अलग से भेजे जाएंगे।

मारे गए श्रद्धालु को मुआवजा न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी महाकुंभ मेला को बीते जनवरी माह में मौनी अमावस्या पर्व पर भगदड़ में एक श्रद्धालु की मृत्यु के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में लिए गए निर्णय की कॉपी 13 नवंबर को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने रामकली बाई की याचिका पर उसके अधिवक्ता अरुण यादव और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल को सुनकर दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी याची के पति मोहनलाल अहिरवार की मृत्यु महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ में हुई थी। ?याची ने याचिका के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को याची के पति की मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की।

कोर्ट को बताया गया कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही याची को उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है और अब उसके पास पति के शव का पंचायतनामा भी है फिर भी उसे कोई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ?अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया है कि याची को गत 22 सितंबर को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर को मेला अधिकारी महाकुम्भ मेला प्रयागराज के समक्ष अपने दावे के समर्थन में उसके पास मौजूद सभी सामग्री के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। क्योंकि उसके दावे का आवेदन मेला अधिकारी द्वारा विचाराधीन है।

कोर्ट को नोटिस के पर्याप्त तामीला का कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं मिला और याची के अधिवक्ता अरुण यादव ने कहा कि सुनवाई के एक दिन पहले तक याची को किसी नोटिस की जानकारी नहीं थी। इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल से नोटिस की कॉपी याची के अधिवक्ता अरुण यादव को ?सुनवाई के दौरान ही दिलाई। साथ ही निर्देश दिया कि नोटिस के जवाब में याची अपने पति की महाकुंभ 2025 के मौनी अमावस्या पर्व के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु के संबंध में उसके पास उपलब्ध सभी सामग्री के साथ 30 अक्टूबर को मेला अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। साथ ही नोटिस के तहत मांगी गई सभी सामग्री के साथ याची के उपस्थित होने पर मेला अधिकारी कानून के अनुसार याची के लंबित आवेदन का निपटारा करते हुए सकारण और तर्कपूर्ण आदेश करें।

मौलाना तौकीर की पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी

» बरेली, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बवाल के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीजेएम अलका पांडेय की कोर्ट में पेशी हुई। तौकीर रजा फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। वहीं से वह वर्चुअल माध्यम से जुड़ा। बरेली पुलिस ने उसे बवाल का मुख्य आरोपी बताया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट ने पेशी के आदेश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार बवाल से संबंधित सभी मुकदमों में रिमांड मंजूर कर ली गई है। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में मौलाना तौकीर को बवाल का मुख्य आरोपी बताया गया है।

आजमगढ़: तस्कर गिरफ्तार एक करोड़ की शराब बरामद

बिहार चुनाव में खपाए जाने की थी तैयारी

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद किया है। इस मामले में दो अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इस शराब को बिहार चुनाव में खपाए जाने की तैयारी थी। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने आज बताया कि कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ी सफलता मिली है।

इस कार्रवाई में 4781.8 लीटर अवैध विदेशी शराब, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। श्री सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई 13 अक्टूबर को प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। आबकारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार कन्नौजिया और एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 229 किमी के पास एक संदिग्ध कंटेनर वाहन में अवैध शराब ले जाई जा रही है।

यह सूचना मिलने के बाद आबकारी और पुलिस टीम टोल प्लाजा के पास पहुंची और 232 किमी टोल प्लाजा के पास वाहन को रोका गया। पूछताछ में चालक भीमा राम (25) और सहयोगी योगेश कुमार (24) ने स्वीकार किया कि वे चंडीगढ़ से बिहार शराब तस्करी कर रहे थे। वाहन की जांच में 537 पेटियों में 2724 बोतल (750 मिली), 4032 बोतल (375 मिली), और 6816 बोतल (180 मिली) शराब बरामद हुई।

जांच में पता चला कि शराब की बोतलों पर लगे क्यूआर कोड और वाहन के चेसिस नंबर में फर्जीवाड़ा किया गया था। अभियुक्तों ने बताया कि वे आशु और राहुल नामक व्यक्तियों के इशारे पर तस्करी कर रहे थे। उनके पास से 4600 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और कंटेनर वाहन भी जब्त किया गया।